

हरिसत में होने वाली मौत

यह एडिटरियल 04/07/2022 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Technology is no panacea for custodial deaths" लेख पर आधारित है। इसमें हरिसत में होने वाली मौतों (Custodial Deaths), पूछताछ प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के आगमन और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

पुलिस बर्बरता और हरिसत में की जाने वाली हिसा के मामले में भारत का बदतर रिकॉर्ड रहा है। वर्ष 2001 से 2018 के बीच पुलिस हरिसत में 1,727 लोगों की मौत हो गई लेकिन इन मामलों के लिए केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया।

- अपराधों की जाँच हेतु वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने पर समय और धन के वृहत् व्यय के बावजूद [हरिसत में मौतें](#) होना आम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिसकर्मी अलग-अलग पृष्ठभूमि और अलग-अलग दृष्टिकोणों के मानव हैं।
- इस संदर्भ में, हरिसत में होने वाली मौतों से जुड़े प्रश्नों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

हरिसत में होने वाली मौतों से हमारा क्या तात्पर्य है?

- हरिसत में होने वाली मौतें या 'कस्टडियल डेथ' (Custodial Deaths) से तात्पर्य है पुलिस हरिसत में अथवा मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायिक हरिसत में अथवा कारावास में दंड भोगने के दौरान व्यक्तियों की मृत्यु।
 - यह बात गुप्त नहीं है कि पुलिस जब अपनी पूछताछ के दौरान प्राप्त नष्कर्षों से संतुष्ट नहीं होती तो कई बार यातना और हिसा का भी सहारा लेती हैं जिससे संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है।
 - इसमें पुलिस हरिसत या कारावास में यातना, मौत और अन्य ज्यादतियाँ शामिल हैं।

भारत में हरिसत में होने वाली मौतों का परदृश्य

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, पछिले 20 वर्षों में देश भर में हरिसत में 1,888 मौतें हुईं, पुलिसकर्मियों के वरिद्ध 893 मामले दर्ज किये गए और 358 पुलिसकर्मियों के वरिद्ध आरोप पत्र दाखल किये गए। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इसी अवधि में केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को छोड़कर पूरे देश में में और कहीं भी इस तरह की मौतों के लिए किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया था।
- हरिसत में होने वाली मौतों के अतिरिक्त, वर्ष 2000 और 2018 के बीच पुलिस के वरिद्ध 2,000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किये गए थे और उन मामलों में केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था।

हरिसत में होने वाली मौतों के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?

- **प्रबल कानून का अभाव:**
 - भारत में अत्याचार वरिधी कानून (Anti-torture Legislation) मौजूद नहीं है, न ही हरिसत में हिसा (Custodial Violence) को अपराध घोषित किया गया है, जबकि दोषी पुलिसकर्मियों/अधिकारियों के वरिद्ध कार्रवाई की स्थिति भी असंतोषजनक है।
- **संस्थागत चुनौतियाँ:**
 - संपूर्ण कारागार प्रणाली अंतरनहित रूप से अस्पष्ट है और पारदर्शिता को कम अवसर देती है।
 - भारत अतिवांछित कारागार सुधार लाने में भी वफिल रहा है और कारागार बदतर स्थिति, भीड़भाड़, कर्मियों की भारी कमी और जेलों में हिसा/आघात के वरिद्ध न्यूनतम सुरक्षा उपायों के अभाव से ग्रस्त बने हुए हैं।
- **चरम बलप्रयोग:**
 - राज्य यातना देने सहित चरम बलप्रयोग की प्रवृत्ति रिखता है जिसका शिकार हाशिये पर स्थिति समुदाय होते हैं। राज्य आंदोलनों में भाग लेने वाले या विचारधाराओं का प्रचार करने वाले उन लोगों को नयित्तरित करने के लिए भी बलप्रयोग का सहारा लेता है जनिहें राज्य अपने वरिद्ध

मानता है या खतरे के रूप में देखता है।

- **सुदीर्घ न्यायिक प्रक्रियाएँ:**
 - अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली सुदीर्घ, महंगी औपचारिक प्रक्रियाएँ गरीबों और कमजोरों को हतोत्साहित करती हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय मानक का अनुपालन नहीं:**
 - हालाँकि भारत ने वर्ष 1997 में अत्याचार के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Convention against Torture) पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि (Ratification) नहीं की है।
 - जबकि यह हस्ताक्षर केवल संधि में नरिधारित दायित्वों की पूर्ति के प्रति देश की मंशा को इंगित करता है, इसकी पुष्टि अनुसमर्थन के बाद ही प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु कानूनों और तंत्रों के नरिमाण का मार्ग प्रशस्त होगा।

हरिसत (Custody) के संबंध में कौन-से प्रावधान उपलब्ध हैं?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **अनुच्छेद 21:**
 - अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के तहत यातना से संरक्षण एक मूल अधिकार है।
 - **अनुच्छेद 22:**
 - अनुच्छेद 22 "कुछ दशाओं में गरिफ्तारी और नरिोध से संरक्षण" प्रदान करता है।
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के वधि व्यवसायी से परामर्श लेने और प्रतिरक्षा कराने का मूल अधिकार भी प्राप्त है।
- **वधि प्रावधान:**
 - **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code- CrPC):**
 - CrPC की धारा 41 को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया और इसमें सुरक्षा उपाय शामिल किये गए ताकि पूछताछ के लिए गरिफ्तारी एवं हरिसत हेतु उचित आधार एवं दस्तावेजी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, गरिफ्तारी को परिवार, दोस्तों एवं आम जनता के लिए पारदर्शी बनाया जा सके तथा कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा प्रदान किया जाए।
 - वर्ष 1972 का मथुरा केस:
 - मथुरा बलात्कार केस हरिसत में बलात्कार (custodial rape) का एक संगीन मामला था जो 26 मार्च, 1972 को घटित हुआ। मथुरा नामक आदवासी लड़की का कथित तौर पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के देसाईगंज पुलिस स्टेशन के परिसर में दो पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार किया गया था।
 - इस मामले ने भारत सरकार को देश में बलात्कार कानूनों में संशोधन के लिए प्रेरित किया और वर्ष 1983 में बलात्कार से नपिटने वाले आपराधिक कानूनों में एक नई श्रेणी जोड़ी गई।
 - कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि महिला कहती है कि उसने यौन संबंध के लिए सहमत नहीं दी थी तो अदालत यही मानकर सुनवाई करेगी कि वह सच कह रही है।
 - मथुरा केस ने बंद कार्यावाही के रूप में इन-कैमरा ट्रायल का भी मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद बलात्कार पीड़ितों को उनके वास्तविक नाम से चिह्नित किये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
 - हरिसत में बलात्कार को परभाषित करने के अलावा, संशोधन ने आरोप लगाने वाले से सबूत का बोझ आरोपी पर स्थानांतरित कर दिया।
 - यह प्रावधान भी किया गया कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद महिलाओं को थाने नहीं बुलाया जा सकता।

हरिसत में पूछताछ के संबंध में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **ब्रेन फगिरप्रटि सिस्टम (BFS):**
 - BFS एक प्रकार की लाई-डिटिक्शन तकनीक है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की मस्तषिक तरंगों को मापा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय कोई व्यक्ति सच कह रहा है या नहीं।
 - यह तकनीक जाँच एजेंसियों को जटिल मामलों में सुराग खोजने में मदद करती है।
- **रोबोट:**
 - नगरिनी के लिए और बम का पता लगाने के लिए पुलिस वभिग द्वारा रोबोट का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
 - कई वशिषज्ञ मानते हैं कि पूछताछ में रोबोट मानव पूछताछकर्ता के समान या उससे बेहतर भूमिका निभा सकते हैं।
 - संभव है कि संदिग्ध व्यक्ति सच उजागर करने के लिए पुलिस की तुलना में स्वचालित संवादी रोबोटों के प्रति अधिक ग्रहणशील हों।
 - AI और सेंसर तकनीक से लैस रोबोट संदिग्धों के साथ एक सहज संबंध बना सकते हैं, चापलूसी, शर्मसार करने और दबाव डालने जैसी प्रेरक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज का रणनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं।
 - ऐरज़ोना विश्वविद्यालय ने एक स्वचालित पूछताछ प्रौद्योगिकी का विकास किया है जिसे 'Automated Virtual Agent for Truth Assessments in RealTime (AVATAR)' नाम दिया गया है।
 - यह पूछताछ के दौरान संदिग्ध की आँखों की गतिविधियों, आवाज़ और अन्य बातों की परख के लिए दृश्य, श्रवण, नकिट-अवरकृत और अन्य सेंसर का उपयोग करता है।
- **AI:**
 - आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) पूछताछ के उपकरण के रूप में उभर रहे हैं। AI मानवीय भावनाओं का पता लगा

सकता है और व्यवहार का पूर्वानुमान कर सकता है।

- जब पुलिस संदिग्धों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही हो तो ML तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सचेत कर सकता है।

■ संबंधित चर्चाएँ:

- प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ही पूरवाग्रह का जोखिम, स्वचालित पृष्ठताछ रणनीति से संबद्ध शंका, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा व्यक्तियों एवं समुदायों को लक्षित करने का खतरा और नगिरानी हेतु इसके दुरुपयोग का संकट मौजूद है।
- जबकि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों में लगातार सुधार हो रहा है, यह एक सीमति साधन ही है जो हरिसत में होने वाली मौतों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता।

आगे की राह

■ भारत को 'यातना के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' की पुष्टि करनी चाहिए।

- यह किसी भी प्रकार की गरिफ्तारी, हरिसत या कारावास के लिए वचिारणीय व्यक्तियों के संबंध में हरिसत और उसके प्रति व्यवहार के औपनिवेशिक नियमों, वधियों, प्रथाओं और व्यवस्थाओं की एक व्यवस्थित समीक्षा को अनिवार्य करेगा।
- इसका अर्थ यह भी होगा कि पीड़ितों के लिए 'बोर्ड ऑफ वजिटर्स' जैसी संस्थाओं के अलावा नविरण और मुआवजे की वशिष व्यवस्था स्थापति की जाएगी।

■ पुलिस सुधार:

- स्वतंत्रता से वंचित करने संबंधी मामलों में शामिल अधिकारियों को शक्ति करने और प्रशिक्षण देने के लिए भी दशानरिदेश तैयार कथि जाने चाहिए क्योंकि यातना को प्रभावी ढंग से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि पुलिस तंत्र का वरिष्ठ स्तर ऐसे मुद्दों की गंभीरता का अनुमान नहीं लगाएगी और वर्तमान अभ्यासों में बदलाव नहीं लाएगी।

■ कारागार तक पहुँच:

- स्वतंत्र और योग्य व्यक्तियों को वस्तुस्थिति की समीक्षा और नरीक्षण के लिए हरिसत/नरीध स्थलों तक असीमति और नयिमति पहुँच की अनुमति दी जानी चाहिए।
- पुलिस थानों (पृष्ठताछ कक्ष सहित) में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ।
- गैर-आधिकारिक आगंतुकों (Non-Official Visitors- NOVs) द्वारा औचक नरीक्षण को भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए जो हरिसत में यातना के वरिद्ध एक नविरक उपाय के रूप में कार्य करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2015 में श्री दलीप के. बसु मामले में अपने ऐतहासिक नरीणय में इसका सुझाव दया था।

■ वधिआयोग की 273वीं रिपोर्ट का कार्यानवयन:

- रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि हरिसत में प्रताड़ना करने के आरोपति—चाहे वे पुलिसकर्मी हों, सैन्य या अर्द्धसैन्य बल के कर्मी हों, पर केवल प्रशासनिक कार्रवाई के बजाय आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि एक प्रभावी नरीध की स्थापना हो।

■ अन्य उपाय:

- नीति निर्माताओं द्वारा कानूनी अधिनियमों, प्रौद्योगिकी, जवाबदेही, प्रशिक्षण और सामुदायिक संबंधों, सभी को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की जानी चाहयि।
- पुलिस ज्यादतियों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी सहायता पाने के संवैधानिक अधिकार और निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार आवश्यक है।
 - इसके लिए हर थाने/कारागार में डसिप्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डगि लगाना उपयुक्त होगा।
- यदि भारत वधि के शासन द्वारा शासति समाज के रूप में बने रहना चाहता है तो न्यायपालिका के लिए यह अनिवार्य है कि वह अत्यधिक वशिषाधिकार प्राप्त और सबसे कमज़ोर लोगों के बीच न्याय की पहुँच के अंतराल को भरने के उपाय करे।
 - भारत में न्याय की अभगम्यता केवल एक आकांक्षी लक्ष्य नहीं है, न्यायपालिका को इसे व्यावहारिक रूप से साकार करने के लिए सरकार के वभिन्न अंगों के साथ मलिकर कार्य करने की ज़रूरत है।

अभ्यास प्रश्न: जाँच के वैज्ञानिक तरीके अपनाने से लेकर पुलिसिकर्मियों को प्रशिक्षण देने तक के वृहत प्रयासों के बावजूद भारत में हरिसत में मौतें आम परदिश्य हैं। टपिपणी करें।